

लोहिया जी के राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता

सीमा शर्मा, शोधार्थिनी
डॉ हरीश कुमार वैश्य, शोध निर्देशक
श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला

लोहिया जी एक ऐसे चिंतक थे जिनके विचारों में उस समय के अन्याय के प्रति आवाज उठाने का दृढ़ संकल्प था। लोहिया जी जितने चिंतित वर्तमान को लेकर थे उतनी ही चिंता उन्हें भविष्य की थी। उनकी कल्पना भविष्य को लेकर केवल व्यक्ति व देश तक ही सीमित नहीं थी बल्कि वह खुले दिमाग के ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आज की राजनीति में लोहिया जी जैसे विचारक को खोजना अपने आप में भूसे में सुई खोजने जैसा है परंतु यह इतना असंभव भी नहीं कि समाजवाद में उनके भी विचारों को खोजा ना जा सके। लोहिया जी एकमात्र ऐसे विचारक थे जिन्होंने एक साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में तत्कालीन समस्याओं पर प्रकाश डालने का कार्य किया और ऐसे सवाल उठाए जो उस समय की वर्तमान सरकार को उस स्थिति के बारे में खुली चुनौती थी। लोहिया जी ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो लोकतंत्र, राजनीतिक शिक्षा व्यवस्था आदि के क्षेत्र में कुछ कहने में सफल हो पाए थे। लोहिया जी जब सन 1964 में पहली बार चुनकर लोकसभा गए तो उन्हीं के द्वारा एक ऐतिहासिक बहस छेड़ी की हमारे यहां 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि तीन आने रोज पर अपना गुजारा करते हैं। जबकि गरीब देश का प्रधानमंत्री ₹26000 रोज खर्च करता है। वही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आम जनता के विषय में आवाज उठाई और देश के प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया की वे गरीब जनता को और गरीब बनाने का कार्य कर रहे हैं। वे पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही हैं जो गरीब जनता के अनुकूल नहीं है उनसे अमीर और अमीर बन रहा है गरीब अभी भी गरीब बना हुआ है। सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं विभागीय स्तर पर उलझ कर रह जाती हैं उनका गरीब जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाता। जिस कारण हमारे देश का गरीब गरीब ही रह जाता है और अपने स्तर से नहीं उठ पाता। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही **अन्न धन योजना** के तहत पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता जबकि अपात्र जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें बाजार भाव में बेच देते हैं। जिसके कारण गरीब सुविधाओं के अभाव में भूखा मरने लगता है। सरकार को चाहिए की सर्वेक्षण के आधार पर सही पात्रों को योजना का लाभ दिला कर गरीब जनता को उनके स्तर से उठाने का कार्य करें।

लोहिया जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे या यूं कहें कि वह अहिंसा के पुजारी थे। निर्दोष जनता पर गोली चलाने को वह गलत समझते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी ही सरकार से इस्तीफे की मांग कर ली थी उस समय की सरकार ने जो भयानक हिंसा का परिचय दिया था उनकी नजर में गलत था। वे एक ऐसे समाजवादी और ईमानदार नेता थे जिन्होंने अपनी ही सरकार को घेरे में ला खड़ा किया था। लोहिया जी हिंसा की अपेक्षा सिविल नाफरमानी और अहिंसा को व्यापक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर बल देते रहे उनका कहना था कि **मारेगें नहीं परंतु मरेंगे भी नहीं**। इस कथन का तात्पर्य है अपनी बात बिना किसी हिंसा के भी मनवाने का प्रयास करेंगे। लोहिया जी निरंतर सत्याग्रह और अहिंसा को व्यापक रूप से स्थापित करने के पक्षधर थे। लोहिया जी निस्त्रीकरण पर भी उतना ही बल देते थे। उनका कहना था कि हथियारों पर खर्च करने की अपेक्षा इतना धन जनता पर खर्च किया जाए तो उचित होगा। उनका मानना था कि हिंसा से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा इसीलिए अहिंसा को अपनाना चाहिए। लोहिया जी का कहना था कि जिस प्रकार मौजूदा समय में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन हो रहा है उससे तो सुख और शांति की स्थापना नहीं हो पाएगी। जबकि लोहिया जी शांत जीवन जीने के समर्थक थे। इसीलिए वह समय-समय पर निस्त्रीकरण को अपनाने पर बल देते थे। परंतु दुनिया में जितनी तेजी के साथ आणविक हथियारों का निर्माण हो रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वर्तमान समय में कोई भी युद्ध होता है तो उसके भयानक परिणाम संपूर्ण विश्व को भुगतने पड़ेंगे स्थिति अधिक भयंकर हो जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसके भयंकर परिणाम भुगतेंगे। इसीलिए लोहिया जी ने समय-समय पर हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग करते थे। लोहिया जी ने युद्ध के भयंकर परिणामों को करीब से देखा था इसीलिए वह शस्त्रों के निर्माण को कम करने पर जोर देते रहे। यदि वर्तमान समय में उनके इस कथन का विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होता है कि उनके इस कथन का



पतन होता जा रहा है। प्रत्येक देश अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जैविक हथियारों का निर्माण दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। जब हथियारों का निर्माण हो रहा है तो आने वाले समय में उनके उपयोग की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएंगी। जबकि हमारी सरकार मौलिक मुद्दों से हटकर केवल शक्ति प्रदर्शन पर भी अधिक धन खर्च कर रही है जिससे जन और धन को आने वाले भविष्य में आर्थिक संकट की संभावना है। एक छोटे से युद्ध में भी यदि इन हथियारों का प्रयोग किया गया तो अधिक जनहानि की संभावना है। अतः सरकार को चाहिए और हथियारों के निर्माण की अपेक्षा निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाए और मुख्य मुद्दों पर धन को खर्च किया जाए। यदि सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो जिस देश पर अधिक आणविक शक्ति होगी तो कमजोर देश को उसका गुलाम बनकर रहना होगा। हम या कोई भी कमजोर देश आने वाले समय में गुलामी की दाता को झेलने के लिए तैयार होगा। इसीलिए समय रहते सरकार को चाहिए कि हथियारों के निर्माण पर अधिक खर्च ना करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर बल देना होगा